



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 49] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 4—दिसम्बर 10, 2004 (अग्रहायण 13, 1926)
No 49] NEW DELHI, SATURDAY, DEC. 4—DEC. 10, 2004 (AGRAHAYANA 13, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	993	भाग II—खण्ड 3 उपखण्ड—(iii)—भारत सरकार पृष्ठ के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियों को शामिल है) के हिन्दी प्राविष्ट पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों को नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1245	भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	3	भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, निर्यंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1411
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों को नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1683	भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्रवाई द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	8837
भाग II—खण्ड I—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन श्रवण द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग II—खण्ड 1 क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक विनियमों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	6505
भाग II—खण्ड 2—विशेषक तथा विशेषकों पर प्रवर समितियों के विल तथा रिपोर्ट	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निगमों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	613
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्जाने वाला सम्पुरक	*
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*		

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

Page

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .. 993

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .. 1245

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence .. 3

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .. 1683

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations ..

PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinance and Regulations ..

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills ..

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..

Page

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories) ..

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India. 1411

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .. 8837

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners .. —

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .. 6505

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .. 613

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi ..

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिसर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 नवम्बर 2004

सं० एफ० 11-2/2004-एम सी(पो):—जबकि भारत सरकार अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों के वंचन या उल्लंघन में संबंध में शिकायतों की जांच करने, उनको पसन्द की शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने और संचालित करने और किसी अनुसूचित केन्द्रीय विश्वविद्यालय से सीधे सहायता प्राप्त करने हेतु अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था को अनुमति प्रदान करने संबंधी अल्पसंख्यकों की मांगों से भली भांति निवेदिता है।

2. अतः अब भारत सरकार तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग का गठन करती है, जैसे कि 11 नवम्बर, 2004 को प्रख्याति 2004 के आदेश संख्या 6 की धारा 3 के तहत परिचालना की गई है।

3. आयोग के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार के होंगे :—

(i) अल्पसंख्यकों को शिक्षा से संबंधित कोई प्रश्न जो इसके पास भेजा गया हो, तत्केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार को परामर्श देना।

(ii) अल्पसंख्यकों को पसन्द की शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने और संचालित करने और निम्न अनुसूचित विश्वविद्यालय से सम्बद्धन संबंधों हिसाब विवाद के संबंध में विशिष्ट शिक्षादत्तों का जर्ज करना और कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार को इसके निष्कर्षों से अवगत करना।

(iii) ऐसे कार्य करने जो आयोग के सभी अर्थात् किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में आवश्यक, प्रासंगिक अथवा सहायक हो सकते हैं।

4. आयोग अल्पसंख्यक शिक्षा और किसी अनुसूचित विश्वविद्यालय के बीच सम्बन्धन के मामले के संबंध में संवैधानिक आयोग के रूप में विवाद समाधान मंच के रूप में कार्य करेगा और उच्चतम विवेक अतिरिक्त होगा और सब एक इतना पालन करेगा। इस आयोग को अपने कार्यों के निष्पत्ति के लिए निम्न प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत एक सिविल न्यायालय का शक्तियां प्रदान की जाएंगी।

5. इस आयोग में एक अध्यक्ष तथा दो सदस्यों को मिलाकर तीन व्यक्ति होंगे। यथासंभव, सभी सदस्यों का चयन अल्पसंख्यक समुदायों से किया जाएगा। अध्यक्ष के लिए चाहिए कि वह किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत रहा हो। सदस्यों को व्यक्तिगत या योग्य तथा निष्ठावान होना चाहिए। अध्यक्ष सहित सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।

6. (I) कोई सदस्य किसी समय सहस्रलिखित रूप से केन्द्र सरकार को संवाचित करे हुए अध्यक्ष अथवा, सदस्य के कार्यभार से त्यागपत्र दे सकता है।

(II) केन्द्र सरकार किसी व्यक्ति को सदस्य के पद से हटा सकती है यदि वह व्यक्ति—

(क) एक अनुक्त दिवालिया हो जाता हो

(ख) उसे उस आदेश के लिए अभियुक्त बनाया गया हो तथा कारावास का सजा सुनाई गई हो जो केन्द्र सरकार का राय में तलित चरित्रहीनता का मामला हो;

(ग) जो मानसिक रूप से अक्षम हो जाता हो तथा तत्संबन्ध घोरणा किंजो सक्षम न्यायालय द्वारा कर ली गई हो;

(घ) कार्य करने से मना कर देता हो अथवा कोई निष्पादन का दृष्टि से अक्षम हो जाता हो;

(ङ) आयोग से अनुपस्थिति के लिए अवकाश प्राप्त किए बिना आयोग को लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहा हो; अथवा

(च) केन्द्र सरकार को राय में उसने अक्षम अथवा संस्थ के पद का दुरुपयोग किया हो और उस प्रकार उसका पद पर बने रहना अनैतिक में नुपमानेहो।

बसंत कि किसी व्यक्ति को इस अनुच्छेद के तहत तत्काल पदच्युत नहीं किया जाएगा जब तक उसे इस आयोग को सुनने की अवसर प्रदान नहीं किया गया हो।

7. अध्यक्ष को राज्यमंत्री का दर्जा तथा सदस्यों को भारत सरकार के सचिव का दर्जा प्राप्त होगा। आयोग के अध्यक्ष, सदस्य तथा कर्मचारों भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के

अंतर्गत जन सेवक होंगे। आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को प्रतिमाह 45000/- रु० की संचित पालिब्ध प्रदान की जाएगी। वे आवास किराया भत्ते, याता भत्ते, चिकित्सा, टेलीफोन सुविधाओं, जो भारत सरकार के एक सचिव को अनुज्ञेय हैं, के पत्र होंगे।

8. अध्यक्ष तथा सदस्यों को दिए जाने वाले वेतन तथा भत्ते और इस अध्यादेश के खंड 6 में उल्लिखित सचिव, अधिकारियों तथा अन्य वर्गकर्मियों को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन संबंधी व्ययों सहित प्रशासनिक व्यय उस अनुदान राशि में से किए जायेंगे जो केन्द्र सरकार इस प्रयोजनार्थ उचित समझे तथा प्रदान करें।

9. यह आयोग किसी प्राधिकरण, संगठन अथवा व्यक्ति से ऐसी जानकारी प्राप्त कर सकता है जो वह आवश्यक अथवा इस विषयवस्तु हेतु प्रासंगिक समझे।

10. यह आयोग अपने स्वयं को कार्यविधि अपना सकता है और वह जब कभी भी आवश्यक समझे भारत के किसी भी भाग का दौरा कर सकता है।

11. इस आयोग का मुख्यालय दिल्ली में स्थित होगा।

यह भी अध्यादेश दिया जाता है कि अम सूचनार्थ इस अधिसूचना को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

च० बालाकृष्णन,
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 16th November 2004

No. F. 11-2/2004-MC(P).—Whereas the Government of India has been seized of the demand of the Minorities to look into the complaints regarding deprivation or violation of the Constitutional rights of the minorities to establish and administer educational institutions of their choice and to permit a minority educational institution to seek direct affiliation to a scheduled Central University.

2. Now, therefore, the Government of India are pleased to constitute the National Commission for Minority Educational Institutions, with immediate effect, as envisaged under Sec. 3 of the Ordinance No. 6 of 2004 promulgated on the 11th Nov. 2004.

3. The terms of reference of the Commission shall be as follows :—

(i) To advise the Central Government or any State Government, on any question relating to the education of minorities, that may be referred to it;

(ii) To look into specific complaints regarding deprivation or violation of the rights of minorities to establish and administer educational institutions of their choice, and any dispute regarding affiliation to a Scheduled University and to report its findings to the Central Government for implementation; and

(iii) to do such acts and things as may be necessary, incidental or conducive to the

attainment of all or any of the objects of the Commission.

4. The Commission would act as the forum of dispute resolution in the form of a Statutory Commission regarding matters of affiliation between a minority educational institution and a Scheduled University and its decision shall be final and binding on the parties. The Commission would be granted the powers of a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 for the purpose of discharging its functions.

5. The Commission would consist of three members comprising a Chairperson and two Members. All the Members should, as far as possible, be chosen from among the minority communities. The Chairperson should have been a Judge of a High Court. The Members should be persons of eminence, ability and integrity. The term of the Members, including the Chairperson, would be five years.

6. (i) A Member may, by writing under his hand addressed to the Central Government, resign from the office of Chairperson or, as the case may be, of Member at any time.

(ii) The Central Government shall remove a person from the office of Member if that person—

(a) becomes an undischarged insolvent;

(b) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude;

(c) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court;

(d) refuses to act or becomes incapable of acting;

(e) is, without obtaining leave of absence from the Commission, absent from three consecutive meetings of the Commission; or

(f) in the opinion of the Central Government, has so abused the position of Chairperson or Member as to render that person's continuance in office detrimental to the public interest;

Provided that no person shall be removed under this clause until that person has been given an opportunity of being heard in the matter.

7. The Chairman will have the status of a Minister of State and the Members of the Commission will have the status of a Secretary to the Government of India. The Chairman, Members and staff of the Commission shall be public servants within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code. The Chairman and Members of the Commission shall be paid a consolidated emolument of Rs. 45000/- per month. They shall be entitled to HRA, TA, Medical, telephone facilities, etc. as admissible to a Secretary to the Government of India.

8. The salaries and allowances payable to the chairperson and Members and the administrative expenses, including salaries, allowances and pensions payable to the Secretary, officers and other employees referred to in section 6 of the Ordinance, shall be paid out of the grants of such sums of money, as the Central Government may think fit and provide, for being utilised for such purposes.

9. The Commissions shall obtain such information, as it may deem necessary or relevant to the subject matter, from any authority, organization or individual.

10. The Commission may adopt its own procedure of working and may visit any part of India, as and when considered necessary.

11. The Headquarters of the Commission shall be in New Delhi.

Ordered also that the notification be published in the Gazette of India for general information.

C. BALAKRISHNAN
Joint Secretary